

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/५०-८६/३५५००—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं इन्डस्ट्रीयल एण्ड एलाइंड प्रोडक्ट्स कारपोरेशन प्लाट नं० ४५, सैक्टर ६, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सोहन लाल, मार्फत श्री के० एल० शर्मा, जी-१५ ओल्ड प्रैस, कलोनी, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बदल लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

और चंकि हरियाणा के राजप्रधान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछतीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रीधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-गी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, करीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

कथा श्री सोहन लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित यथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/५०-८६/३५४७२.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डस्ट्रीयल एण्ड एलाईंड प्रोडक्ट्स कारपोरेशन, प्लाटनं० ४५, सैक्टर ६, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरी चन्द मार्फत श्री के० एल० शर्मा, जी-१५, श्रौल्ड प्रैस कलोनी, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाव विलित मामले में कोई ग्रोवर्सिक विवाद है;

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की घारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अर्थवा सम्बन्धित मामला है:—

इया श्री द्वारी चंद की सेवाओं का समापन त्यायोचित नहीं थी क्योंकि वह नहीं तो वह किस राहत का हक्कदार नहीं?

संशोधित/एफोडी०/५०-८६/३५४७।—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैंने इण्डस्ट्रीयल एण्ड एलाइंसोडक्ट्स कारपोरेशन, प्लाट नं० ४५, सेक्टर-६, प.रीदाबाद, के श्रमिक श्री चिरंजी लाल मार्फत श्री क० एल० शर्मा, जी-१५ शौल्ड प्रैस क्लोनी, प.रीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है;

और चैकिं इंग्लिश के गण्यपाल विद्याद को ल्यायतिर्णय देव निर्दिष्ट करना बांधनीय समझते हैं :

इसलिए, अब, अधिकारीयिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 प.रवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम व्यायालय, प.रीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला व्यायनिर्णय एवं पंचाटीत मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री चिरंजी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का वक्ता है?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/५०-८६/३५४८६।—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डस्ट्रीयल एण्ड एलाइंड प्रोडक्ट्स कारपोरेशन, प्लाट नं० ४५, सैक्टर-६, परीदावाद के श्रमिक श्री गिरजि मार्फत श्री कै० एल० शर्मा, जी-१५, शॉल्ड प्लैस क्लोनी परीदावाद तथा उसके प्रत्यक्षकों के मध्य इसमें इसके बाबू लिखित सामले में कोई श्रीबोगिक विवाद है:

और चंकि इतिहास के राज्यपाल उक्त विवाद को व्याप्तिरूप हेतु विद्विष्ट करना बांधनीय समझते हैं :

इस लिये, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, परीदावाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधिकारी सम्बन्धित मामला। है :—

क्या श्री गिर्ज की सेवाओं का समापन व्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हृकदार है ?